करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

नवंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **5**

- राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना 5
- 'जोरन' 5
- राज्य अलंकरण पुरस्कार, 2021 6
- छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव 7
- खैरागढ़ से विधायक देवव्रत सिंह का निधन 8
- गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ देश के पाँच शीर्ष राज्यों में शामिल 8
- भोपाल-रायपुर-भोपाल उड़ान शुरू 8
- राज्यपाल को झीरम घाटी जाँच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई 9
- हसदेव बांगो जलविद्युत गृह में रिकॉर्ड उत्पादन 9
- मदन सिंह चौहान को मिला पद्म श्री सम्मान 10

नोट :

- सी-मार्ट 10
- पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को पद्मश्री 10
- कोविड टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल 11
- बस्तर ज़िले में 4जी मोबाइल टावर का शिलान्यास 11
- मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कास्ट और रसोईया मानदेय की राशि के अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ 12
- विद्यार्थियों की ट्रैकिंग हेतु वेबसाइट 12
- दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार 13
- स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का लगातार तीसरे साल उत्कृष्ट प्रदर्शन 13
- छत्तीसगढ़ जनजातीय क्राफ्ट मेला 14
- टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 14
- छत्तीसगढ़ में 699 नए मोबाइल टावर को मंज़ूरी 14
- 'प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड' 15
- छत्तीसगढ़ को मिला स्वच्छतम् राज्य का अवार्ड 15

नोट :

- सीजी कैंप पोर्टल 16
- बाल्को ने सीमेंट निर्माण के लिये पहली फ्लाई-ऐश रैक भेजी 17
- गाय के गोबर से पेंट का निर्माण करेगा छत्तीसगढ़ 17
- चिराग परियोजना 18
- मुख्यमंत्री ने किया थिंक बी के नए कार्यालय का शुभारंभ 18
- मुख्यमंत्री ने वेलनेस टूरिज्म की सुविधा का किया शुभारंभ 19
- नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स जारी : रायपुर नगरीय क्षेत्र फ्रंट रनर 19
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर 20
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 21
- 'महात्मा फुले समता पुरस्कार' 21
- माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ 21
- नगरी दुबराज को मिला जीआई टैग 22

नोट :

छत्तीसगढ़

राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

- 1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के अवसर पर 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' और 'गोधन न्याय योजना' के अंतर्गत राज्य के 21 लाख ग्रामीण किसानों को 1510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया।

प्रमुख बिंदु

- इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि 1500 करोड़ रुपए तथा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गोठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को दी जाने वाली लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपए शामिल है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन सालों में राज्य के किसानों ने धान का भरपूर उत्पादन किया है और सरकार ने भी भरपूर धान की खरीदी की है। तीन सालों में हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। इस साल एक करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद है।
- उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिये पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 नवंबर, 2021 तक कर दिया है।
- कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रोत्साहन से राज्य में उतेरा और रबी फसलों की खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ा है। इस साल रबी सीजन में 2 लाख 80 हज़ार हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य है।

'जोरन'

चर्चा में क्यों ?

- 1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना' के ऑनलाइन डैशबोर्ड और महिला स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार किये गए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मॉर्ट फूड वर्जन 'जोरन' का गिफ्ट पैक लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को नागरिकों के लिये और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से स्लम स्वास्थ्य योजना का डैशबोर्ड लांच किया गया है।
- मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के ऑनलाइन डैशबोर्ड से नागरिक घर बैठे ही मुफ्त में इलाज कराने हेतु अग्रिम अपॉइनमेंट ले सकेंगे। साथ ही देख पाएंगे की मोबाइल मेडिकल यूनिट की गाड़ी उनके एरिया में कब आने वाली है।
- इस डैशबोर्ड पर मरीजों की दवा पर्ची और जाँच रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिये नागरिकों को ऑनलाइन डैशबोर्ड पर पंजीयन कराना होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर एक वर्ष पहले 1 नवंबर, 2020 को राज्य के स्लम क्षेत्रों के नागरिकों को नि:शुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना' की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को उनके मोहल्ले में ही इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। मात्र एक वर्ष में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिये 11 लाख से अधिक नागरिकों का मुफ्त में उपचार कर उन्हें स्वास्थ लाभ दिया जा चुका है।

नोट :

- शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रायपुर शहर की स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने 'जोरन' ब्रांड नेम से मिलेट स्मार्ट फूड तैयार किया है। 'जोरन' में बाजरा की बर्फी, दरभा कॉफी और रागी के कुकीज, बाजरा और बस्तर के काजू के कुकीज, मिलेट से बने पीड़िया, पपची, ठेठरी जैसे 14 स्मार्ट फूड उत्पाद शामिल किये गए हैं।
- छत्तीसगढ़ में बेटी को विवाह के समय उपहार स्वरूप झांपी में रखकर व्यंजन देने की परंपरा है, जिसके नाम पर इस गिफ्ट पैक का नामकरण 'जोरन' किया गया है।
- त्योहारों के मौके पर लोग एक-दूसरे को उपहार देने इस गिफ्ट पैक का उपयोग कर सकेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा मिलेट से बने उत्पादों को पौष्टिक एवं स्मार्ट फूड की संज्ञा दी गई है।

राज्य अलंकरण पुरस्कार, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 1 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर आयोजित राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव के समापन समारोह पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों को उनकी उपलब्धियों एवं राज्य के विकास में योगदान देने के लिये राज्य अलंकरण सम्मानों से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इस बार 31 विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया।
- राज्य अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियों के नाम इस प्रकार हैं-
- आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त
  - शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार - जानकी प्रसाद पुलस्त (ज़िला- बिलासपुर)
  - गुरु घासीदास सम्मान - पुरानिक लाल चेलक (ज़िला- दुर्ग)
  - हाजी हसन अली सम्मान - जनाब रौनक जमाल (ज़िला- दुर्ग)
  - भँवर सिंह पोर्ते सम्मान - जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़
- गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदत्त
  - पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान - कुंदनलाल गौर (ज़िला- दुर्ग)
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त
  - यति यतनलाल सम्मान - रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर
  - पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान - सुश्री विद्या राजपूत (ज़िला- रायपुर)
  - महाराजा अग्रसेन - सुश्री के.एम. नायडू (ज़िला- बस्तर)
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त
  - गुंडाधूर सम्मान - कुमारी रोहणी साहू (ज़िला- बिलासपुर)
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त
  - मिनीमाता सम्मान - डॉ. सुश्री कल्पना देशमुख (ज़िला- दुर्ग)
- सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त
  - ठाकुर प्यारेलाल सम्मान - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर
- कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त
  - डॉ. खूबचंद बघेल सम्मान - मुकेश चौधरी (ज़िला- रायगढ़)

नोट :

- समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त
  - दानवीर भामाशाह सम्मान - भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधीवार्ड (ज़िला- मुंगेली)
- मत्स्य विभाग द्वारा प्रदत्त
  - श्रीमती बिलासाबाई केंवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार - अनिल कुमार साहू (ज़िला- दुर्ग)
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त
  - संस्कृत भाषा सम्मान - डॉ. तोयनिधि वैष्णव (ज़िला- रायपुर)
- श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त
  - महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान - प्रसेनजीत साहा, वी. जनार्दनराव, रामलाल और दीपक कुमार पंडित (एनटीपीसी थर्मल पॉवर स्टेशन जमनीपाली कोरबा)
- ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त
  - बिसाहूदास महंत पुरस्कार वर्ष 2018-19 - सुनील कुमार और राजाराम देवांगन (ज़िला- जांजगीर-चांपा)
  - बिसाहूदास महंत पुरस्कार वर्ष 2019-20 - तुकाराम देवांगन और श्रीराम देवांगन (ज़िला- जांजगीर-चांपा)
  - राजराजेश्वरी करूणामाता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार - राजेश कुमार देवांगन एवं टीकाराम देवांगन (ज़िला- बलौदाबाज़ार भाटापारा)
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त
  - धनवंतरि सम्मान - डॉ. के.बी. श्रीनिवास राव (ज़िला- रायपुर)
- जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदत्त
  - चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार - अंबु शर्मा (प्रिंट मीडिया हिन्दी) (ज़िला- दंतेवाड़ा) एवं अंशुमान शर्मा (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिन्दी)
  - मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार - टिकेश्वर पटेल (प्रिंट मीडिया अंग्रेज़ी) (ज़िला- रायपुर)
  - पं. माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान - मृणाल पांडे (टीकमगढ, मध्य प्रदेश)
- विधि एवं विधायी विभाग द्वारा प्रदत्त
  - बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान - ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह (ज़िला- बलौदाबाज़ार) एवं कुमारी शमीम रहमान (ज़िला- रायपुर)
- संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त
  - पं. सुंदरलाल शर्मा सम्मान - नंदकिशोर तिवारी (ज़िला- बिलासपुर)
  - चक्रधर सम्मान - प्रभंजय चतुर्वेदी (ज़िला- दुर्ग) एवं सुनील तिवारी (ज़िला- रायपुर)
  - दाऊ मंदराजी सम्मान - काशीराम साहू (ज़िला- बिलासपुर) एवं रेखा देवार (ज़िला- मुंगेली)
  - देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार - हृदय प्रकाश अनंत (ज़िला- जांजगीर-चांपा) और अमोलदास टंडन (ज़िला- दुर्ग) (वर्ष 2021 के लिये)
  - देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार - गौकरण दास बघेल (ज़िला- दुर्ग)
  - किशोर साहू सम्मान - मनमोहन सिंह ठाकुर (ज़िला- रायपुर)
  - किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण - अपूर्व बड़गैय्या (मुंबई)

छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

- 1 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये हर साल आदिवासी महोत्सव तर्ज़ पर छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस महोत्सव के आयोजन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की जयंती (राष्ट्रीय युवा दिवस) 12 जनवरी, 2022 से होगी, जो तीन दिनों तक चलेगी।
- इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुडुख, सरगुजी सहित सभी लोक भाषा-बोलियों के साहित्यकारों को बड़ा मंच प्रदान किया जाएगा, वहीं पंडवानी, भरथरी, सुआ व पंथी के साथ ही प्राचीन नाचा-गम्मत के लोक कलाकारों को भी मंच मिलेगा।

खैरागढ़ से विधायक देवव्रत सिंह का निधन

चर्चा में क्यों ?

- 3 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के पूर्व शाही परिवार के सदस्य और खैरागढ़ सीट से वर्तमान विधायक देवव्रत सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 52 साल के थे।

प्रमुख बिंदु

- देवव्रत सिंह राजनांदगाँव ज़िले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता कॉन्ग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) पार्टी के विधायक थे।
- विधायक देवव्रत सिंह खैरागढ़ विधानसभा सीट से चार बार विधायक निर्वाचित हुए थे। वह एक बार राजनांदगाँव लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष भी थे।
- इसके अलावा वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 1995 से 1998 तक खैरागढ़ से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1998 से 2003 तक पहले वे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे।

गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ देश के पाँच शीर्ष राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021' में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासन वाले शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित (बेस्ट गवर्नेंस) राज्यों की सूची में चौथा स्थान दिया गया है। वहीं, स्थिरता सूचकांक (सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स) में राज्य ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 के अनुसार केरल ने 1.618 अंक के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ ने 0.872 स्कोर कर देश में चौथा स्थान हासिल किया है।
- इस इंडेक्स में राज्यों के विकास, इक्विटी और स्थिरता संकेतकों को देखकर तथा उसका मूल्यांकन कर नंबर दिया गया है।
- छत्तीसगढ़ 0.946 स्कोर के साथ स्थिरता सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। स्थिरता सूचकांक संसाधनों तक पहुँच और उपयोग के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान किया जाता है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव जाति पर पड़ता है।
- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है।

भोपाल-रायपुर-भोपाल उड़ान शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 2 नवंबर, 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर भोपाल-रायपुर मार्ग पर इंडिगो एयरलाइंस की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के निदेशक राकेश रंजन सहाय ने कहा कि उड़ान सप्ताह में तीन दिन- मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी।
- भोपाल से फ्लाइट सुबह 10.15 बजे रवाना होगी और दोपहर 12 बजे रायपुर पहुँचेगी। फ्लाइट दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर रायपुर से रवाना होगी और दोपहर 1.35 बजे भोपाल पहुँचेगी।
- पहले दिन भोपाल से 59 यात्री और रायपुर से 63 यात्री रवाना हुए।

राज्यपाल को झीरम घाटी जाँच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई

चर्चा में क्यों ?

- 6 नवंबर, 2021 को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जाँच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई। यह रिपोर्ट आयोग के सचिव एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने पर विवाद भी शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे तथा वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।
- यह प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4,184 पेज में तैयार किया गया है।
- झीरम घाटी की घटना 25 मई, 2013 को हुई थी। इस घटना की जाँच के लिये आयोग का गठन 28 मई, 2013 को किया गया था। आयोग ने 8 साल बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है।
- हालाँकि जाँच आयोग द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को देने की जगह सीधे राज्यपाल को दिये जाने पर विवाद शुरू हो गया है, विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर आयोग द्वारा यह रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जानी चाहिए थी, ताकि सरकार की तरफ से इसे सदन में पेश किया जा सके।
- कॉन्ग्रेस ने रिपोर्ट सौंपने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब भी किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है, तब आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है।
- उल्लेखनीय है कि बस्तर की झीरम घाटी में नक्सलियों ने 25 मई, 2013 को तत्कालीन कॉन्ग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित करीब 32 अन्य लोग शहीद हो गए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज़ के दौरान निधन हो गया था।

हसदेव बांगो जलविद्युत गृह में रिकॉर्ड उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

- 6 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने अक्टूबर माह में सर्वाधिक 90.10 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह एक महीने के दौरान अब तक के अधिकतम उत्पादन का रिकॉर्ड है। अक्टूबर में बिजली उत्पादन 100.92 प्रतिशत क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) रहा। इस दौरान ज़ीरो ट्रिपिंग के साथ शत-प्रतिशत प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पीएएफ) हासिल किया गया।
- उल्लेखनीय है कि इससे पहले हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने अगस्त 2020 में 87.743 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान सीयूएफ 98.278 प्रतिशत था।
- विद्युत उत्पादन कंपनी के बांगो जल विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। इसमें 40-40 मेगावाट की तीन इकाइयाँ क्रियाशील हैं।

नोट :

मदन सिंह चौहान को मिला पद्म श्री सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 8 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मदन सिंह चौहान को वर्ष 2020 के लिये कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कारों के लिये कुल 141 लोगों का चयन किया गया था, जिनमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण तथा 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिये चुना गया था
- वर्ष 2020 के ये पद्म पुरस्कार कोविड-19 महामारी की वजह से प्रदान नहीं किये जा सके थे, जिन्हें 8 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

सी-मार्ट

चर्चा में क्यों ?

- 9 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विकास के लिये गाँवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की नई पहल करते हुए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग को निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुम्भकारों एवं अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इनकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग के लिये शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।
- सी-मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि इसके लिये प्रथम चरण में सभी ज़िला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हज़ार वर्गफुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हज़ार वर्गफुट में आधुनिक शो रूम की तरह सी-मार्ट की स्थापना की जाए।
- इसके लिये उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध किसी शासकीय भवन का उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों में यदि उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो, वहाँ कलेक्टर, उद्योग विभाग अथवा वन विभाग को अच्छी लोकेशन में आवश्यकतानुसार भूमि आवंटित किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट के लिये उपलब्ध भवनों के अपग्रेडेशन अथवा नए भवन के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं की विभागीय राशि, सी.एस.आई.डी.सी. अथवा लघु वनोपज संघ की राशि उपयोग करने को कहा है।
- मुख्यमंत्री ने 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के उत्पादों की तरह ही इन वस्तुओं की मार्केटिंग की व्यवस्था लघु वनोपज संघ द्वारा करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने ज़िला कलेक्टरों को महिला समूहों द्वारा निर्मित एवं अन्य सभी पारंपरिक उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रेंडिग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ से समन्वय करने को कहा है।

पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को पद्मश्री

चर्चा में क्यों ?

- 9 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के ख्यातिप्राप्त पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डॉ. बारले को यह सम्मान वर्ष 2021 के लिये प्रदान किया गया है।
- गौरतलब है कि 8 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार मदन सिंह चौहान को वर्ष 2020 के लिये पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था।
- डॉ. राधेश्याम बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन-जन तक पहुँचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, अपितु देश को गौरवान्वित किया है।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. बारले का जन्म दुर्ग ज़िले की पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर, 1966 को हुआ था। इन्होंने एम.बी.बी.एस. के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। डॉ. बारले को उनकी कला साधना के लिये इससे पहले भी कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
- गौरतलब है कि डॉ. राधेश्याम बारले प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के पंजीकृत लोक कलाकार हैं।

कोविड टीकाकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल

चर्चा में क्यों ?

- 9 नवंबर, 2021 को कोरोना वैक्सीनेशन में रायगढ़ ज़िले ने शत-प्रतिशत टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है।

प्रमुख बिंदु

- रायगढ़ ज़िले में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी, 2021 को हुई थी। मात्र 298 दिनों में ज़िले ने शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
- रायगढ़ ज़िले में 10 लाख 68 हज़ार 456 लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य था, जिसे पूरा करते हुए इतने लोगों को टीके के दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। ज़िले में अब तक पहली व दूसरी डोज मिलाकर कुल 21 लाख 47 हज़ार 169 टीके लगाए गए हैं।
- रायगढ़ ज़िला टीकाकरण के मामले में पूरे प्रदेश में शुरू से अव्वल रहा है और आज की उपलब्धि ने ज़िले को टीकाकरण के मामले में न केवल राज्य में शीर्ष स्थान प्रदान किया है, बल्कि रायगढ़ ने देश के ऐसे टॉप ज़िलों में अपनी जगह बनाई है, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आबादी को टीका की दोनों डोज लगा चुके हैं।
- रायगढ़ के लिये 26 जून का दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन पूरे प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक एक लाख 43 हज़ार से अधिक लोगों को टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया।

बस्तर ज़िले में 4जी मोबाइल टावर का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर ज़िले के सद्रबोडेनार गाँव में 4जी मोबाइल टावर लगाने के लिये शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- आर.के. गढ़वाल, उप महानिदेशक (अनुपालन), डीओटी, छत्तीसगढ़ ने दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की एक परियोजना के हिस्से के रूप में 4जी मोबाइल टावर की नींव रखी।
- गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) की परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के 14 नक्सल प्रभावित ज़िलों में 848 करोड़ रुपए की लागत से कुल 971 टावर लगाए जाएंगे।

नोट :

- 4जी सक्षम मोबाइल टावरों के चालू होने से ब्रॉडबैंड की पहुँच बढ़ेगी और कई गाँवों को कवरेज प्रदान करने तथा डिजिटल विभाजन को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज वामपंथी उग्रवाद से निपटने में गेम चेंजर साबित हो सकता है।

मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कास्ट और रसोईया मानदेय की राशि के अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 11 नवंबर, 2021 को स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कुकिंग कास्ट एवं रसोईया मानदेय राशि भुगतान के ऑनलाइन अंतरण प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। कुकिंग कास्ट की राशि बैंक के माध्यम से स्कूलों के बच्चों के खाते में ट्रांसफर होगी।

प्रमुख बिंदु

- मध्याह्न भोजन की वेबसाइट में जैसे-जैसे बच्चों के खातों की जानकारी अपलोड होती जाएगी, उसके बाद यह राशि उनके खातों में ट्रांसफर होगी।
- इसी प्रकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस वित्तीय वर्ष से मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कास्ट और रसोईया मानदेय राशि का भुगतान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है। इसके लिये राज्य स्तर से एक्सिस बैंक के माध्यम से राशि का भुगतान सीधे 87 हज़ार रसोईयों और मध्यान्ह भोजन के संचालनकर्त्ता लगभग 44 हज़ार समूहों के खातों में ट्रांसफर करने की शुरुआत की गई है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रीष्मावकाश में भी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिये जाने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार द्वारा 39 दिनों के लिये कुकिंग कास्ट की राशि बच्चों को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत ग्रीष्म अवकाश (1 मई, 2021 से 15 जून, 2021) की अवधि का कुल 39 दिनों के लिये कुकिंग कास्ट की राशि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जा रही है।
- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन राशि का आवंटन राज्य को नहीं मिला है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से राशि जारी करने की प्रत्याशा में राज्य के 28 लाख 76 हज़ार बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा राशि प्रदान की जा रही है।
- प्रदेश में प्राथमिक स्कूल के 17 लाख 97 हज़ार और मिडिल स्कूल के 10 लाख 79 हज़ार बच्चों को यह राशि प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रति छात्र प्रति दिवस 5 रुपए 19 पैसे की दर से और मिडिल स्कूल के बच्चों को प्रति छात्र प्रति दिवस 7 रुपए 45 पैसे की दर से राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 67 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि बच्चों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

विद्यार्थियों की ट्रैकिंग हेतु वेबसाइट

चर्चा में क्यों ?

- 11 नवंबर, 2021 को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रदेश में संचालित 'एकलव्य' और 'प्रयास' विद्यालयों से पढ़कर निकले बच्चों की ट्रैकिंग के लिये बनाई गई वेबसाइट http://eklavya.cg.nic.in/ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस वेबसाइट को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और एनआईसी ने मिलकर तैयार किया है।
- ट्रैकिंग के माध्यम से प्रयास आवासीय स्कूल और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल से 5 वर्ष पूर्व पढ़कर निकले बच्चे वर्तमान में क्या कर रहे हैं (शासकीय, अशासकीय नौकरी या स्वयं का व्यवसाय या अन्य कार्य कर रहे हैं), इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी।
- गौरतलब है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्यस्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, रायपुर द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है।

नोट :

दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 12 नवंबर, 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वर्ष 2020 के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ ने तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेल प्रेस का चयन किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिये अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिये अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोज़गार के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी/एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर-सरकारी संगठन या कार्यालय के लिये समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है।

स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का लगातार तीसरे साल उत्कृष्ट प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य को सूचित किया है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने पुन: स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वर्ष 2019 एवं 2020 में भी छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अग्रणी राज्य था।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ पर 20 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविद द्वारा छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने इस बार भी बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ को न सिर्फ राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरों को भी इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य होगा, जिसके सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत किए जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र प्रदेश है, जहाँ पर नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदियों द्वारा घर-घर से 1600 टन गीला एवं सूखा कचरा एकत्रीकरण करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ओडीएफ प्लस राज्य निरूपित किया गया है।
- भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हर साल देश के समस्त शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है।
- मुख्य रूप से घर-घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी आधार पर राज्यों एवं शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा शहरों को पुरस्कृत किया जाता है।

नोट :

छत्तीसगढ़ जनजातीय क्राफ्ट मेला

चर्चा में क्यों ?

- 15 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय टेकाम ने वीर जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर रायपुर के हाट बाजार पंडरी में राज्य स्तरीय तीन दिवसीय जनजातीय क्राफ्ट मेला का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से इस जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया जा रहा है।
- जनजातीय क्राफ्ट मेला के आयोजन का उद्देश्य जनजातीय शिल्प एवं कला कौशल को संरक्षित रखना, इनका संवर्धन करना और जनजातीय कौशल को सामान्य जनों के बीच प्रचारित-प्रसारित करना है।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि मेला में जनजातीय लोक कलाकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने तथा शिल्पकारों को उनके उत्पाद को विक्रय करने का अवसर मिलेगा। विभिन्न सांस्कृतिक दलों का प्रतिदिन यहाँ मंच पर प्रदर्शन होगा, जिसमें उन्हें अपने सांस्कृतिक विचारों का आदान-प्रदान करने का भी अवसर भी प्राप्त होगा।
- उन्होंने बताया कि मेला में प्रदेश के बस्तर से लेकर सरगुजा के कलाकार अपनी कला का तथा शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।
- मेला में जूट, काष्ठ कला, लोह कला, बाँस शिल्प, ढोकरा आर्ट, भित्ती चित्र, गोदना आदि के स्टॉल में प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में आने वाले लोग तथा स्थानीय जन सामान्य भी आदिवासी संस्कृति, परंपरा से परिचित हो सकेंगे।
- विभिन्न जनजातियों के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। बिलासपुर, गरियाबंद, राजनांदगाँव, जगदलपुर, नारायणपुर, अंबिकापुर, जशपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी आदि ज़िलों के कलाकार, शिल्पकार, नृतक दल शामिल होंगे।

टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर

चर्चा में क्यों ?

- 15 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ ने अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय और यूनिसेफ द्वारा बाल संरक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम में एक टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1800-123-6010 शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर किशोर अपराध पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा बाल सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
- इस अवसर पर बाल सुरक्षा पर आधारित नौ वीडियो दिखाए गए। चित्रकला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
- उल्लेखनीय है कि बाल दिवस को चिह्नित करने के लिए राज्यव्यापी श्बाल सुरक्षा सप्ताहश् शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य माता-पिता और नागरिकों को बच्चों की सुरक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है।
- इसके तहत बाल मजदूरी और भीख मांगने के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। तथा पीड़ित बच्चों को छुड़ाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में 699 नए मोबाइल टावर को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 17 नवंबर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िलों के अछूते गाँवों में मोबाइल सेवाओं के लिये कुल 699 टावर लगाए जाने को मंज़ूरी दी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के साथ ही आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी ज़िलों में भी मोबाइल सेवाओं के लिये मंज़ूरी दी है।
- छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िलों में 4G आधारित मोबाइल सेवाओं के लिये कुल 699 टावर लगाए जाएंगे, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्तपोषित हैं।
- परियोजना के तहत बस्तर ज़िले में 71, बीजापुर ज़िले में 176, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ज़िले में 85, कोरबा ज़िले में 20, महासमुंद ज़िले में 7, नारायणपुर ज़िले में 171, राजनांदगाँव ज़िले में 57 और उत्तर बस्तर कांकेर ज़िले में 112 टावर लगाए जाएंगे।
- इस परियोजना में आत्मनिर्भरता के लिये उपयोगी डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल उन्नयन एवं विकास, आपदा प्रबंधन, ई-गवर्नेंस पहल, उद्यमों और ई-कॉमर्स सुविधाओं की स्थापना, ज्ञान साझा करने और उपलब्धता के लिये शैक्षिक संस्थानों को पर्याप्त समर्थन का प्रावधान करने तथा नौकरी के अवसर और डिजिटल इंडिया के विज़न को पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

'प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड'

चर्चा में क्यों ?

- 19 नवंबर, 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के चार किसानों को पौधों की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण के लिये 'प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड'से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कृत किसानों में लिंगुराम ठाकुर (बीजापुर), दीनदयाल यादव (जांजगीर-चांपा), हेतराम देवांगन (जांजगीर-चांपा) और संजय प्रकाश चौधरी (बालोद) शामिल हैं।
- कृषि मंत्री ने इन किसानों को अवार्ड के साथ ही 1.50 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया।
- किसान लिंगुराम ठाकुर ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धान की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- दीनदयाल यादव को 36 सब्जियों की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण और प्रचार के लिये सम्मानित किया गया, जबकि हेतराम देवांगन को साई करेला और साई लौकी की स्वदेशी किस्मों के संरक्षण एवं प्रचार के लिये सम्मानित किया गया।
- संजय प्रकाश चौधरी को पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर जैविक खेती के लिये नवीन प्रयोगों का उपयोग करके अरकर दुबराज (धान) के संरक्षण के लिये सम्मानित किया गया। ये धान की 11 पारंपरिक किस्मों की जैविक खेती करते हैं, जो जैविक तरीके से अपनी सुगंध और स्वाद के लिये जानी जाती हैं।
- यह पुरस्कार हर साल पौधों की किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को उन किस्मों के उत्पादन को बचाने और बढ़ावा देने के लिये दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ को मिला स्वच्छतम् राज्य का अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 20 नवंबर, 2021 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम् राज्य का अवार्ड प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अवार्ड ग्रहण किया।

प्रमुख बिंदु

- यह आयोजन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के भाग के रूप में किया गया था।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष देश के सभी शहरों एवं राज्यों के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। इसमें आकलन के लिये विभिन्न मापदंड निर्धारित किये गए हैं।
- इनमें से मुख्य रूप से घर-घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं। इन्हीं मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है और रैंकिंग के आधार पर शहरों एवं राज्यों का प्रदर्शन तय होता है। उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले शहर और राज्य को उसकी श्रेणी के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।
- वर्ष 2019 और 2020 के बाद लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में अव्वल होने का गौरव हासिल किया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती-2021 श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड छत्तीसगढ़ के नाम रहा। वहीं विभिन्न श्रेणियों में दिये जाने वाले 239 पुरस्कारों में से सर्वाधिक 67 निकायों को पुरस्कार प्राप्त हुए।
- छत्तीसगढ़ के 67 निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले। इनमें अंबिकापुर को सेल्फ सस्टेनेबल स्माल सिटी (एक लाख से तीन लाख आबादी में श्रेणी द्वितीय), रायपुर को फास्टर मूवर स्टेट कैपिटल, भिलाई-चरोदा को क्लीनेस्ट सिटी (50 हज़ार से एक लाख आबादी में श्रेणी प्रथम), बीरगाँव को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस (50 हज़ार से एक लाख आबादी में श्रेणी चौथा स्थान) में पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
- चिरमिरी को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, भाटापारा को फास्टेस्ट मूवर सिटी (50 हज़ार से एक लाख आबादी में श्रेणी द्वितीय), कवर्धा को क्लीनेस्ट सिटी (25 हज़ार से 50 हज़ार आबादी में श्रेणी प्रथम), बेमेतरा को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जशपुर नगर को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी (25 हज़ार से 50 हज़ार आबादी में श्रेणी द्वितीय), दीपिका को फास्टेस्ट मूवर सिटी (25 हज़ार से 50 हज़ार आबादी में श्रेणी तृतीय), पाटन को क्लीनेस्ट सिटी (25 हज़ार से कम आबादी में श्रेणी प्रथम) में पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
- इसी प्रकार दोरनापाल को बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक, चंद्रपुर को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, उतई को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी (25 हज़ार से कम आबादी में श्रेणी पाँचवा स्थान) एवं अभनपुर को फास्टेस्ट मूवर सिटी (25 हज़ार से कम आबादी की श्रेणी) में पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
- स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान रैंकिंग के आधार पर शहरों को तीन और पाँच सितारा (3 एंड 5 स्टार कैटेगरी) श्रेणी में भी रखा गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के दो शहर-अंबिकापुर और पाटन को पाँच सितारा श्रेणी में शामिल किया गया है, वहीं 44 अन्य शहरों को 3 सितारा रैंकिंग दी गई है।
- स्वच्छता के लिये काम करने के दौरान छत्तीसगढ़ ने जहाँ स्वच्छता अभियान को नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना से जोड़ा, वहीं 6-आर पॉलिसी को अपनाया। छत्तीसगढ़ में 6-आर पॉलिसी के लिये रीथिंक, रियूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस और रिफ्यूज को आधार बनाकर काम किया गया।
- इसका परिणाम यह रहा कि अपशिष्ट बनने की मात्रा में कमी हुई और अपशिष्टों का उचित प्रबंधन हुआ। दूसरी ओर सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए, जिससे ओडीएफ में भी मदद मिली। इधर गोधन न्याय योजना भी ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में सफाई के साथ आमदनी बढ़ाने में मददगार बनी।

सीजी कैंप पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

- 22 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पूर्व सीजी कैंप पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा-गरुवा- घुरवा-बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।

नोट :

- सीजी कैंप पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी ज़िले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति, ज़िलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकता है।
- इससे एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य किया जाएगा।
- आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिये जन-शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। जन-शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है।
- शिकायतों की जानकारी, निदान और मॉनिटरिंग के लिये ज़िलेवार, विभागवार जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।

बाल्को ने सीमेंट निर्माण के लिये पहली फ्लाई-ऐश रैक भेजी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत एल्युमिनियम कंपनी (बाल्को) ने कम कार्बन वाले सीमेंट के उत्पादन में सहायता के लिये एक सीमेंट निर्माता को फ्लाई-ऐश की अपनी पहली रैक भेजी। इसका उद्देश्य लाभकारी तरीके से शत-प्रतिशत फ्लाई-ऐश का उपयोग सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

- बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और निदेशक अभिजीत पाति ने बताया कि कंपनी आसपास के कई सीमेंट निर्माताओं को फ्लाई-ऐश की आपूर्ति कर रही है, लेकिन रेलवे के माध्यम से यह पहला प्रेषण था।
- कंपनी ने संयंत्र के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिये हरे कंक्रीट समाधान का उपयोग करने हेतु विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इसके अलावा कंपनी ने फ्लाई-ऐश वाली सड़कों के निर्माण के लिये 'भारतमाला प्रोजेक्ट' के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ भी साझेदारी की है।
- पाति ने कहा कि फ्लाई-ऐश थर्मल पावर उत्पादन का एक बड़ा उपोत्पाद है, जो न केवल टिकाऊ निर्माण में मदद करेगा, बल्कि लंबे समय तथा पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा।

गाय के गोबर से पेंट का निर्माण करेगा छत्तीसगढ़

चर्चा में क्यों ?

- 21 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में गाय के गोबर से प्राकृतिक रंग के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट (जयपुर), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य गो सेवा आयोग ने गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में सालाना 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की उम्मीद है। अनुमानित कमाई हर साल करीब 45 करोड़ रुपए होगी।
- वर्तमान में प्राकृतिक पेंट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 120 रुपए प्रति लीटर है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोठानों में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य उत्पादों का उपयोग बिजली पैदा करने में किया जा रहा है।

नोट :

चिराग परियोजना

चर्चा में क्यों ?

- 24 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कृषि मड़ई कार्यक्रम में विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली लगभग 1735 करोड़ रुपए लागत की 'चिराग परियोजना' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक धरमपुरा का नामकरण धरमू माहरा के नाम पर और बस्तर हाईस्कूल को जगतू माहरा के नाम पर करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने जगतू माहरा के नाम पर भव्य सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि 'चिराग परियोजना' छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 ज़िलों में लागू की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर-तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक-से-अधिक लाभ दिलाना है।
- परियोजना के अंतर्गत लघुधान्य फसलें, समन्वित कृषि, जैविक खेती को प्रोत्साहन, भू-जल संवर्धन, उद्यानिकी फसलों, बाड़ी और उद्यान विकास, उन्नत मत्स्य और पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन कर अधिक आय अर्जित करने के कार्य किये गए हैं। इसके अलावा विभिन्न कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार उपलब्धता के भी प्रयास किये जाएंगे।
- परियोजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार की सुराजी योजना के गोठानों को केंद्र में रखकर किया जाएगा।
- इस परियोजना के लिये विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास हेतु स्थापित संस्था आईएफएडी ने वित्तीय सहायता दी है। विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए, आईएफएडी द्वारा 486.69 करोड़ रुपए की सहायता इस परियोजना के लिये दी गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30 प्रतिशत राशि (518.68 करोड़ रुपए) अपने राजकीय कोष से उपलब्ध कराई है।
- चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाज़ार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा ज़िलों के आदिवासी विकासखंडों में लागू किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि एवं सहयोगी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का (कृषि मेला) अवलोकन भी किया और यहाँ के प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की।
- उन्होंने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया।
- कृषि मेले में कृषि विज्ञान केंद्र-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लाई फोड़ाई मशीन, लघु धान्य फसल बुआई यंत्र, हल, मेंड़ बनाने का यंत्र, कोदो वीडर, पैडी वीडर, साईकिल व्हील, बस्तर कृषि उत्पाद का प्रदर्शन, लघुधान्य फसलों की विभिन्न किस्में, काजू प्रसंस्करण केंद्र आदि का प्रर्दशन किया गया।
- कृषि मड़ई में मछली पालन विभाग, नारियल विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) में हरीहर बाज़ार, डैनेक्स, पशुधन विकास विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न उत्पादों, कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री ने किया थिंक बी के नए कार्यालय का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 24 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एकदिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने, उनके संवर्द्धन और संरक्षण के लिये स्थापित किये गए थिंक बी (टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर नॉलेज बस्तर) के धरमपुरा स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में निर्मित नए कार्यालय का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही पॉलीटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के लिये निर्मित स्मार्ट क्लास और स्मार्ट लैब का शुभारंभ भी किया।
- उल्लेखनीय है कि नवाचार, स्वरोज़गार और उद्यमिता के इच्छुक बस्तर के युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकीय, कानूनी सहित विभिन्न प्रकार की सहायता के लिये थिंक बी की स्थापना की गई है।
- ऐसे युवाओं के लिये प्रशासन की ओर से इनोवेशन कंपनियों की मदद से स्टार्टअप की बुनियादी सुविधाएँ, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार को स्थापित करने में सहायता के साथ-साथ ऑनलाइन-ऑफलाइन पेपर, किताबें, ऑडियो-वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण सहित केंद्रीकृत संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला का आयोजन कर युवाओं को स्वरोज़गार के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इसके साथ ही ज़िला प्रशासन ने आईआईएम रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइस, मुंबई, आईआईआईटी रायपुर और हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ एमओयू किया है।
- आईआईआईटी रायपुर द्वारा स्टार्टअप शुरू करने वाले बेरोज़गारों को टेक्निकल जानकारी तथा आईआईएम जैसे संस्थान स्टार्टअप शुरू करने वाले बेरोज़गारों को मैनेजमेंट सिखाएंगे तो वहीं टाटा कंपनी बिज़नेस की मार्केट वैल्यू, बिज़नेस चल पाएगा या नहीं जैसी जानकारी देगी।
- बिज़नेस शुरू करने के लिये कानूनी जानकारियाँ हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट देंगे। यहाँ स्टार्टअप शुरू करने वाले बेरोज़गारों को पूरी तरह से मुफ्त में मार्गदर्शन और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने वेलनेस टूरिज्म की सुविधा का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 24 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के थिंक बी स्टार्ट अप सेंटर शुभारंभ के अवसर पर वेलनेस टूरिज्म का भी औपचारिक शुभारंभ किया। वेलनेस टूरिज्म के तहत पर्यटकों को स्वस्थ जीवनशैली के लिये मार्गदर्शन एवं परामर्श भी दिया जाएगा। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य के गुर भी सिखाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेलनेस टूरिज्म के ज़रिये देश-विदेश के पर्यटक बस्तर अंचल में आने के लिये आकर्षित होंगे। इससे अंचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ लोगों को आय का ज़रिया भी मिलेगा।
- उन्होंने इस अवसर पर पर्यटन समिति के सदस्यों को आरोग्यम योगा किट का वितरण किया। योगा किट में योगा मैट, एरोमेटिक ऑयल्स, अगरबत्ती, म्यूजिक सिस्टम, दरी, थर्मल स्कैनर, इंडक्शन कुकर, डिफ्यूजर, ग्लव्स आदि शामिल हैं।
- गौरतलब है कि पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें हर संभव सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु ज़िला प्रशासन बस्तर द्वारा लगातार नित नए प्रयोग किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत बस्तर में पर्यटकों के लिये मुख्य पर्यटन स्थलों पर वेलनेस टूरिज्म की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- वेलनेस टूरिज्म का संचालन स्थानीय पर्यटन समितियों के द्वारा योग्य एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के सहयोग से किया जाएगा जिससे स्थानीय ग्रामवासियों को भी अच्छी-खासी आय प्राप्त होगी।

नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स जारी : रायपुर नगरीय क्षेत्र फ्रंट रनर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 'सतत् विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स'में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर नगरीय क्षेत्र को 'फ्रंट रनर'की श्रेणी में रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत् विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स को जारी किया गया है।

नोट :

- इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांको में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें सर्वाधिक 75.5 अंक प्राप्त कर शिमला प्रथम रैंक पर है। रायपुर ने 67.36 अंक प्राप्त कर 20वीं रैंक प्राप्त की है।
- छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस इंडेक्स में रायपुर शहर का स्कोर व रैंक अनेक बड़े व प्रमुख शहरों जैसे- मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ, प्रयागराज, रांची, इंदौर से बेहतर है।
- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत् विकास को सुनिश्चित करने हेतु 17 एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। एसडीजी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश तथा राज्य प्रतिबद्ध हैं।
- राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति के मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा 'एस.डी.जी. स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क'एवं 'एस. डी.जी. बेसलाईन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट' तैयार की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12 जुलाई 2021 को जारी किया गया है। इस फ्रेमवर्क के आधार पर विभागों द्वारा सतत् अनुश्रवण व अनुशीलन रायपुर शहर की इस उपलब्धि में सहायक रहा है।
- 'सतत् विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स'में रायपुर शहर को एस.डी.जी. गोल 12 (रिस्पोंसिबल प्रोडक्शन एंड कंजंप्शन) में सर्वाधिक 86 अंक, गोल 4 (क्वालिटी एजुकेशन) तथा गोल 6 (क्लीन वाटर एंड सेनिटेशन) में 79 अंक प्राप्त हुए हैं।
- इसके साथ ही गोल 7 (अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी), गोल 9 (इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर), गोल 11 (सटेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज), गोल 13 (क्लाईमेट एक्शन) तथा गोल 16 (पीस, जस्टिस एंड स्ट्रोंग इंस्टीट्यूशन) में भी अच्छा स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण रायपुर को 'फ्रंट रनर'की श्रेणी में रखा गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रकाशित इंडिया टुडे पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ वायु, जल प्रदूषण, ठोस कचरे के प्रबंधन और वनों के संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए वर्ष 2021 में पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर रहते हुए वर्ष 2021 में पहले पायदान पर है। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ दी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोहा, कोयला, डोलोमाइट जैसे खनिजों से परिपूर्ण है, जिसके कारण राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार हुआ है। इन उद्योगों की स्थापना से एक ओर जहाँ क्षेत्र के लोगों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है, वहीं इसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट की चुनौतियाँ भी मिल रही हैं।
- राज्य सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जाँचने के लिये 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किये गए हैं।
- वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित तीन प्रमुख नगर निगमों-रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किये गए हैं। वायु में सल्फर की मात्रा 37 प्रतिशत तक कम हो गई है। यह 2016 में 26.02 माइक्रोग्राम थी, जो 2020 में घटकर 16.34 माइक्रोग्राम हो गई।
- इसी प्रकार दैनिक नाइट्रोजन डाईऑक्साइड संकेंद्रण में भी 17 प्रतिशत की कमी आई है। यह 24.11 माइक्रोग्राम से घटकर 19.88 माइक्रोग्राम रह गई है।
- इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिये 27 स्टेशन स्थापित किये हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियों-खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिये 10 स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
- छत्तीसगढ़ की लगभग 28.8 मिलियन आबादी में 6 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों से लगभग एक हज़ार 650 टन ठोस कचरा प्रतिदिन एकत्र होता है। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिशन क्लीन सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
- अंबिकापुर में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण और रिसाइकिलिंग मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। बलौदाबाज़ार ज़िले में भी हानिकारक कचरे के निपटान के लिये अलग से सुविधाएँ विकसित की गई हैं। इसी प्रकार बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिये 4 यूनिट भी प्रस्तावित हैं।

नोट :

- हाल ही में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छतम राज्य के रूप में सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ लगातार तीन सालों से देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है।
- छत्तीसगढ़ राज्य 44 प्रतिशत वनों से आच्छादित है, इससे ग्रीन हाउस के प्रभावों को भी कम करने में मदद मिल रही है, वहीं सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया के 30 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 26 नवंबर, 2021 को केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने छत्तीसगढ़ की पशुपालक माधुरी जंघेल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारु राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय द्वारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक स्वर्गीय वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर गुजरात के आनंद में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किये गए।
- पशुपालन व पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिये भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- गौरतलब है कि धमतरी ज़िले के कुरुद विकासखंड के ग्राम मुरा के कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन दुलारु राम साहू को श्रेष्ठ गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में तीन लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार राजनांदगांव ज़िले के हुईखदान विकासखंड के ग्राम संडी की पशुपालक माधुरी जंघेल को श्रेष्ठ देशी नस्ल कृषक श्रेणी में दो लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

'महात्मा फुले समता पुरस्कार'

चर्चा में क्यों ?

- 28 नवंबर, 2021 को महात्मा फुले की 131वीं पुण्यतिथि (समता दिवस) के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुणे के महात्मा फुले स्मारक समता भूमि में आयोजित समारोह में 'महात्मा फुले समता पुरस्कार'से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा आयोजित इस समारोह में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री बघेल को फुले पगड़ी, मानद शॉल, सम्मान निधि और स्मृति चिह्न से सम्मानित किया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिये गए असाधारण फैसलों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिये इस वर्ष के महात्मा फुले समता पुरस्कार प्रदान किया गया।
- पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री को ज्योतिबा फुले की पुस्तक 'किसान का कोड़ा' की प्रति भी भेंट की गई।
- उल्लेखनीय है कि समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद राजनीति, साहित्य और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिये मशहूर हस्तियों को 'महात्मा फुले समता पुरस्कार'प्रदान करती है।

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 29 नवंबर, 2021 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर ज़िले के विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम केरता स्थित माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि इस सत्र में राज्य सरकार ने गन्ना की दर 355 रुपए प्रति क्विंटल तय की है।
- गन्ना पेराई सत्र 2021-22 में ज़िला- सूरजपुर, सरगुजा (अम्बिकापुर) एवं बलरामपुर के 17 विकास खंडों से गन्ना रकबा 9,374.874 हेक्टेयर से तीन लाख मीट्रिक टन गन्ना पेराई करने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। पंजीकृत 15 हज़ार 310 कृषकों से गन्ना क्रय किया जाएगा।
- गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 के लिये उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण दर रिकवहरी प्रतिशत 9.5 प्रतिशत पर निर्धारित 275.50 रुपए प्रति क्विंटल है।
- राज्य शासन द्वारा गन्ना प्रोत्साहन राशि 79.50 रुपए प्रति क्विंटल कुल 355 प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा, साथ ही रिकवहरी 9.5 प्रतिशत से अधिक होने पर 0.1 प्रतिशत पर 2.90 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि गन्ना पेराई सत्र 2020-21 में ज़िला सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर के 15 विकाख खंडों से गन्ना रकबा 8689.846 हेक्टेयर से 3 लाख मीट्रिक टन पेराई करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध में गन्ना उत्पादक 10,600 कृषकों से कुल 2 लाख 2 हज़ार 617 मीट्रिक टन गन्ना की खरीदी की गई।
- गन्ने खरीदी पर 270.75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य राशि 54 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान कृषकों के बैंक खाता के माध्यम से कर दिया गया है। किसानों को राज्य शासन द्वारा 12 करोड़ 18 लाख 7 हज़ार 422 रुपए का गन्ना बोनस का भुगतान किया जा चुका है।

नगरी दुबराज को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

- 29 नवंबर, 2021 को ग्वालियर में आयोजित जियोग्राफिकल इंडिकेशन कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के धमतरी विकास खंड के नगरी के धान की 'नगरी दुबराज'किस्म को जीआई टैग देने के लिये अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'नगरी दुबराज'छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग, यानी जीआई टैग मिला है। इसके पहले जीरा फूल धान की किस्म के लिये प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है।
- चेन्नई द्वारा गठित कमेटी में भारत के 10 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जाँचा और परखा गया तथा नगरी दुबराज की नगरी में उत्पत्ति होने का प्रमाण स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही इसका प्रमाण-पत्र भी मिल जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2021 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने जीआई टैग के लिये नगरी दुबराज का प्रस्ताव भेजा था।
- नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का प्रयोग किया जाता है।
- नगरी दुबराज की उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी गई है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। विभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज का स्रोत नगरी सिहावा को ही बताया गया है।
- नगरी दुबराज से निकलने वाला चावल बहुत ही सुगंधित है। यह पूर्णरूप से देशी किस्म है और इसके दाने छोटे हैं। इसका चावल पकने के बाद खाने में बेहद नरम है। एक एकड़ में अधिकतम छह क्विंटल तक उपज मिलती है। धान की ऊँचाई कम और 125 दिन में पकने की अवधि है।
- वर्ल्ड इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गनाइज़ेशन (विपो) के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी खास फसल, प्राकृतिक या कृत्रिम उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह बौद्धिक संपदा का अधिकार माना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद ने सन् 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 'जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स'लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य, व्यक्ति या संगठन इत्यादि को दे दिया जाता है।

नोट :